इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में यूपी के चार प्रस्ताव मंजूर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) में यूपी की चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे प्रदेश की देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण राज्यों में स्थिति और मजबूत हुई है।

प्रदेश तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मजबूत केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार की ईसीएमएस योजना के तीसरे चरण में स्वीकृत 22 प्रस्तावों में यूपी के चार प्रस्ताव शामिल होना इसका प्रमाण हैं। इस योजना के तहत देशभर में लगभग 41863 करोड़ रुपये के निवेश और 33791 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना है जिसका सीधा लाभ यूपी की अर्थव्यवस्था और युवाओं को भी मिलेगा। ईसीएमएस के तहत प्रदेश में पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल, लीथियम ऑयन सेल और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण की इकाइयां स्थापित होंगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।

मजबूत होगी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन, आयात पर घटेगी निर्भरता

योगी सरकार द्वारा वर्ष 2017 लागू की गई उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, पारदर्शी नीति और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश आज देश का अग्रणी मोबाइल विनिर्माण का केंद्र बन चुका है। यह देश के 55 प्रतिशत से अधिक स्मार्टफोन और 50 से 60 प्रतिशत मोबाइल कंपोनेंट्स का उत्पादन कर रहा है।

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) सेक्टर से जुड़ी 20 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं। वीवो, ओप्पो, सैमसंग, लावा, हारमन और एलजी जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ कई प्रमुख कंपोनेंट सप्लायर्स ने भी प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं।